बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 141 ● नई दिल्ली ● बुधवार 18 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

बगैर नोटिस किसी के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर, एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया आश्वासन

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उत्तर नगर में हुई झगड़ के दौरान एक युवक की हत्या के मामले में शामिल रहे आरोपितों के घरों में किसी भी अवैध निर्माण को नहीं तोड़ेगा। एमसीडी ने कहा कि आरोपितों को पहले से नोटिस दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एमसीडी ने उक्त जानकारी आरोपित इमरान की मां जरीना की याचिका पर उक्त जवाब दाखिल किया। एमसीडी के रुख को देखते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर आगे की कार्यवाही बंद कर दी। अदालत ने रिकार्ड पर लिया कि याचिकाकर्ताओं को नोटिस दिए बिना एमसीडी अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

लोधी कॉलोनी में बिजली ढांचे का होगा बड़ा अपग्रेड, 9.45 करोड़ की परियोजना से मिलेगी राहत

नई दिल्ली। नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बिजली आपूर्ति को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने यहां बिजली वितरण नेटवर्क के उन्नयन की परियोजना का शिलान्यास किया. इस परियोजना के पूरा होने के बाद इलाके में बिजली कटौती और कम वोल्टेज जैसी समस्याओं से काफी राहत मिलने की उम्मीद है. लोधी कॉलोनी रोड स्थित सेंट्रल पार्क कॉर्नर, मेन मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और सांसद बांसुरी स्वराज ने संयुक्त रूप से परियोजना का शिलान्यास किया. इस अवसर पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के सदस्य अनिल वाल्मीकि और सरिता तोमर, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे. इस पहल का उद्देश्य इलाके में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए आपूर्ति प्रणाली को अधिक भरोसेमंद और स्थिर बनाना है.

पुराने ढांचे के कारण बढ़ रही थीं बिजली समस्याएं

एनडीएमसी के मुताबिक लोधी कॉलोनी गवर्नमेंट फ्लैट्स में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पालिका परिषद संभालती है, जबकि फ्लैट्स के भीतर बिजली का रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जाता है. 1960 के दशक में जब इन फ्लैट्स का निर्माण हुआ था तब प्रत्येक फ्लैट के लिए मात्र एक किलोवॉट बिजली लोड स्वीकृत था. समय के साथ घरेलू उपकरणों और सुविधाओं के बढ़ने से यह मांग अब पांच से दस किलोवॉट प्रति फ्लैट तक पहुंच गई है. पुराने ढांचे के

कारण खासकर गर्मियों में बिजली कटौती, कम वोल्टेज और उतार-चढ़ाव की समस्या अक्सर देखने को मिलती रही है.

करोड़ की योजना से होगा वितरण नेटवर्क अपग्रेड

इन समस्याओं को दूर करने के लिए एनडीएमसी ने लोधी कॉलोनी में बिजली वितरण नेटवर्क के व्यापक उन्नयन की योजना तैयार की है. परिषद ने लो टेंशन केबल की आपूर्ति और बिछाने, 11 किलोवॉट केबल लाइन और स्मार्ट फीडर पिलर स्थापित करने के लिए 9.45 करोड़ रुपये के शुरुआती अनुमान को मंजूरी दी है. इस परियोजना को काउंसिल से औपचारिक स्वीकृति भी मिल चुकी है.

स्मार्ट तकनीक से होगी बेहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल

परियोजना के तहत बिजली आपूर्ति की निगरानी और नियंत्रण को आधुनिक बनाने के लिए स्काडा कम्पैटिबल 40 स्मार्ट फीडर पिलर लगाए जाएंगे. इसके साथ ही कॉलोनी में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 7.5 किलोमीटर एलटी 1.1 किलोवॉट 400 वर्ग मिलीमीटर केबल और 20.120 किलोमीटर एलटी 1.1 किलोवॉट 25 वर्ग मिलीमीटर केबल बिछाई जाएगी. इसके अलावा 33 किलोवॉट अलीगंज (जोर बाग) सब-स्टेशन से लोधी कॉलोनी के पांच ब्लॉकों में स्थित 11 किलोवॉट सब-स्टेशन तक लगभग 0.5 किलोमीटर लंबी 11 किलोवॉट 400 वर्ग मिलीमीटर केबल भी डाली जाएगी. इससे बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और निर्बाध हो सकेगी.

वोल्टेज स्थिर रहेगा

इस आधारभूत ढांचे के उन्नयन से लोधी कॉलोनी में बिजली वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है. वोल्टेज स्थिर रहेगा, बिजली कटौती में कमी आएगी और निवासियों को अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिल सकेगी.

नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम

एनडीएमसी का कहना है कि यह परियोजना शहर के सिविक ईंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और स्मार्ट तकनीक अपनाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. परिषद लगातार अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को अपग्रेड करने और बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है.

एपस्टीन फाइल केस- केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट का तत्काल विवादित पोस्ट हटाने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को दोषी अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है. हिमायनी ने इस बारे में अदालत में याचिका दी है. उन्होंने मानहानि का केस दाखिल करते हुए 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की थी. जस्टिस मिनी पुष्कर्ना ने सोशल मीडिया मंचों पर किसी भी तरह से ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से भी रोक दिया है. हिमायनी पुरी द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहीं जस्टिस ने स्पष्ट किया कि यदि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो मंच ऐसी सामग्री को हटा देंगे या उस तक पहुंच को रोक देंगे. अदालत ने कहा कि हिमायनी पुरी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो

उन्हें अपूरणीय क्षति होगी. हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई अगस्त में तय की है. पुरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि वित्त पेशेवर के रूप में उनकी मुवक्किल की 'वैश्विक प्रतिष्ठा है जिसकी उन्हें रक्षा करनी है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप 'पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण हैं. हिमायनी पुरी ने अपने मुकदमे में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है और कई संस्थाओं को मानहानिकारक सामग्री फैलाने से रोकने का आदेश देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें एपस्टीन और उसके अपराधों से जोड़ने के लिए एक 'समन्वित और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अभियान चलाया गया. उन्होंने आरोपियों से बिना शर्त माफी मांगने और अपने पोस्ट वापस लेने की भी मांग की है. याचिका में कहा गया है कि 22 फरवरी 2026 के आसपास से सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल मंचों, जिनमें 'एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, डिजिटल समाचार पोर्टल और अन्य वेब आधारित प्रकाशन शामिल हैं, पर झूठे, भ्रामक और मानहानिकारक पोस्ट, लेख, वीडियो और सामग्री प्रकाशित और प्रसारित किए गए हैं. हिमायनी पुरी ने दावा किया कि वह एक सफल वित्त और इन्वेस्टमेंट पेशेवर हैं और उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री की बेटी हैं. उनकी याचिका के अनुसार, प्रतिवादियों ने यह 'निराधार आरोप फैलाए कि हिमायनी पुरी के जेफ्री एपस्टीन के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक, वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध थे.

मां-मां में भेद कैसा? गोद लेने वाली माताओं को मातृत्व अवकाश से वंचित करने को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60(4), जो दत्तक माताओं को 12 सप्ताह की मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति केवल तभी देती है जब दत्तक बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो, असंवैधानिक है और दत्तक माता-पिता और बच्चे के लिए समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया कि दत्तक माता को दत्तक बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। पीठ ने कहा कि 2020 संहिता की धारा 60(4), जहां तक ??दत्तक माता को मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए दत्तक बच्चे की उम्र पर तीन महीने की सीमा निर्धारित करती है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मातृत्व लाभ का उद्देश्य मातृत्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने कहा कि इस संदर्भ में तीन महीने से अधिक उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताएं छोटे शिशुओं को गोद लेने वाली माताओं के समान स्थिति में हैं, क्योंकि दोनों को बच्चे के साथ जुड़ाव, देखभाल और समायोजन के लिए समय की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने आगे कहा कि केवल बच्चे की उम्र के आधार पर लाभ से वंचित करना एक कृत्रिम और अनुचित वर्गीकरण है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह प्रावधान बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, गोद लेने के साथ आने वाले महत्वपूर्ण भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक समायोजनों को ध्यान में नहीं रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला प्रावधान लाने को भी कहा। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला अधिवक्ता हम्सानंदिनी नंदूरी द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 60(4) को चुनौती दी थी।

अहंकार और नाटकबाजी, संसद में राहुल गांधी के रवैये पर 204 दिग्गजों ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। देश के 204 पूर्व सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड जज और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा पत्र लिखा है। नागरिकों के नाम लिखे पत्र में राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के हालिया संसद आचरण की कड़ी निंदा की है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि 84 पूर्व नौकरशाहों, 116 पूर्व सैनिकों और पूर्व वकीलों ने जनता को लिखे इस पत्र में कहा है कि संसद में राहुल गांधी का व्यवहार विपक्ष के नेता के पद के लिए उचित नहीं है, जो कि एक अत्यंत जिम्मेदार पद है। उनका व्यवहार अहंकार और विशेषाधिकार की भावना को दर्शाता है। वैद ने आगे कहा वे नाटकबाजी करते हैं; वे संसद की सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी के बीच चाय पीते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद के महत्व को नहीं समझते। हम चाहते हैं कि वे इसे समझें और अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए राष्ट्र से माफी मांगें। स्पीकर ओम बिरला द्वारा सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील के बावजूद, राहुल गांधी नहीं समझते। उन्होंने खुद को हंसी का पात्र बना लिया है।

हम चाहते हैं कि वे एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएं। विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार और विशेषाधिकार की भावना नहीं। 14 मार्च को जो हुआ वह निंदनीय था। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि लोग उनकी बात सुनते हैं। राष्ट्र की आकांक्षाएं संसद में होने वाली चर्चा और उससे बनने वाले कानूनों पर टिकी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन के जवान अजय मलिक से सोमवार को मुलाकात की और कहा कि उन्हें मलिक से बात करके उनके मनोबल और जज्बे को महसूस किया। राहुल गांधी ने आरके पुरम इलाके में मलिक के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने फेसबुक पोस्ट किया, ' आज, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट श्री अजय मलिक जी से मुलाकात की। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल होकर उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। उनसे बातें कर उनका अदम्य साहस, अटूट मनोबल और अद्भुत जज्बा महसूस किया।'' राहुल गांधी ने कहा, ''देश के प्रति उनकी सेवा और समर्पण को मेरा सलाम है। आशा करता हूं वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं।

पीयूष गोयल का बड़ा दावा- पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत

नई दिल्ली।केंद्रीय वाणिय एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत बनी हुई है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए गोयल ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए विश्व भर में उत्साह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 38 देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए गए हैं, जिनसे निर्यातकों को अवसर मिले हैं। मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जब ये सभी मुक्त व्यापार समझौते लागू हो जाएंगे, तो भारतीय निर्यातकों के लिए अपार अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत का माल निर्यात पिछले महीने फरवरी तक स्थिर रहा, लेकिन इसमें गिरावट नहीं आई। गोयल ने कहा कि मार्च के पहले सप्ताह में निर्यात में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन दूसरे सप्ताह में इसमें सुधार हुआ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मार्च के अंत तक भारत अपने निर्यात स्तर को बनाए रखने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मौजूदा वैश्विक स्थिति के मद्देनजर सदन में वाणिय और उद्योग मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा कराई जाए। इन नेताओं का कहना है कि पिछले 16 वर्षों में दोनों मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा नहीं हुई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि ''वर्तमान वैश्विक स्थिति, ऊर्जा संकट और भारत के लिए आगे की चुनौतियों'' को देखते हुए यह चर्चा कराई जानी चाहिए। कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, माकपा, भाकपा, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप), शिवसेना (उबाठा), नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल के नेताओं और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता उच्च सदन के लगभग 100 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विपक्षी सांसद बजट सत्र के पहले भाग से ही विदेश मंत्रालय या वाणिय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा कराने की मांग उठा रहे हैं। अब तक उच्च सदन ने बजट सत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के कामकाज चर्चा की है, और तीन और मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है। पत्र में कहा गया है कि 29 मंत्रालय ऐसे हैं जिन पर 2010 के बाद से चर्चा नहीं की गई है।

क्या अब ट्रैफिक सिग्नल बोलकर बताएंगे कब पार करें सड़क? स्पीकर ने दिल्ली में ऑडिबल सिग्नलों का प्रस्ताव एलजी को भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली में दृष्टिबाधित और बुजुर्ग पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रैफिक सिग्नलों पर ऑडिबल (आवाज आधारित) संकेत लगाने की पहल की गई है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस संबंध में उपराज्यपाल को पत्र लिखकर प्रमुख चौराहों पर ऐसी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है।

पत्र में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दृष्टि संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नलों पर ध्वनि आधारित संकेत लगाने से उन्हें सड़क पार करने में काफी मदद मिल सकती है और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

दिल्ली में लाखों लोग दृष्टि समस्या से प्रभावित

पत्र में बताया गया है कि एम्स के डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थैल्मिक साइंसेज के शोध के अनुसार दिल्ली में करीब 60 लाख लोग किसी न किसी प्रकार की दृष्टि समस्या से प्रभावित हैं। इनमें से लगभग 20 से 30 प्रतिशत लोगों को गंभीर धुंधली दृष्टि

की समस्या है। अनुमान है कि दिल्ली में करीब 12 से 18 लाख लोग लो विजन की समस्या के साथ जीवन जी रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या बुजुर्गों की है।

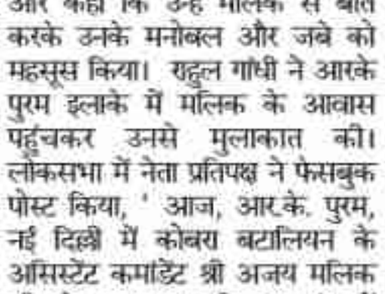

दुनिया के कई देशों में पहले से लागू व्यवस्था

विजेंद्र गुप्ता ने अपने पत्र में कहा कि दुनिया के कई देशों में ट्रैफिक सिग्नलों पर ऑडिबल पैदल यात्री संकेत लगाए गए हैं। ये संकेत बीप या टिक-टिक जैसी ध्वनि के माध्यम से बताते हैं कि सड़क पार करना सुरक्षित है या नहीं। जापान, हांगकांग, सिंगापुर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों में यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू है, जिससे पैदल यात्रियों की सुरक्षा और पहुंच दोनों में सुधार हुआ है।

जापान में संगीत या पक्षियों जैसी आवाज का प्रयोग

कुछ देशों में पैदल पार पथों पर संगीत या पक्षियों की आवाज जैसी ध्वनियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जापान में ट्रैफिक सिग्नलों पर छोटी धुन या पक्षियों जैसी आवाज बजती है, जिससे पैदल यात्रियों को आसानी से संकेत पहचानने में मदद मिलती है और शहर अधिक समावेशी बनते हैं।

प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का अनुरोध

विजेंद्र गुप्ता ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली में दृष्टिबाधित और बुजुर्ग नागरिकों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रमुख चौराहों पर ऑडिबल सिग्नल लगाने से सड़क सुरक्षा और पहुंच में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने इस प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर जल्द लागू करने का अनुरोध किया है।

प्रबंधन लाजवाब है

देश के दस राज्यों में हुए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों ने एक बार फिर भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को स्पष्ट कर दिया है। कुल 37 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में जहां कई उम्मीदवार निर्विरोध जीतकर उच्च सदन पहुंचे, वहीं ग्यारह सीटों पर हुए मुकाबले ने सत्ता और विपक्ष की वास्तविक ताकत को उजागर कर दिया। खासकर बिहार, हरियाणा और ओडिशा में जो नतीजे सामने आए, उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजनीतिक कौशल और संगठनात्मक मजबूती में विपक्ष से कई कदम आगे है। हम आपको बता दें कि इन चुनावों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के कई दिग्गज नेता और अन्य सहयोगी दलों के प्रमुख चेहरे राज्यसभा पहुंचे। वहीं कई राज्यों में विपक्षी दलों के उम्मीदवार या तो निर्विरोध जीत गए या फिर मुकाबले में पूरी तरह पिछड़ गए। लेकिन असली कहानी उन राज्यों में लिखी गई जहां मुकाबला हुआ और वहां विपक्ष की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। बिहार की बात करें तो आपको बता दें कि यहां की पांच सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप कर विपक्ष को करारी शिकस्त दी। यह जीत केवल संख्या बल की नहीं बल्कि रणनीतिक कौशल की भी जीत थी। एनडीए ने पहले से तय कर लिया था कि पांचवीं सीट के लिए दूसरा वरीयता मत निर्णायक होगा और उसी के अनुसार पूरी रणनीति बनाई गई। विपक्ष के पास 41 विधायक थे, लेकिन मतदान के समय चार विधायक गायब हो गए। तीन कांग्रेस और एक राजद विधायक के अनुपस्थित रहने से विपक्ष की पूरी रणनीति ध्वस्त हो गई। दूसरी ओर एनडीए ने अपने सभी 202 विधायकों का मतदान सुनिश्चित कर विपक्ष को पूरी तरह चित कर दिया। दूसरी वरीयता मतों की गिनती में एनडीए उम्मीदवार शिवेश कुमार ने आसानी से जीत हासिल कर ली। यह वही मोड़ था जहां विपक्ष पूरी तरह खेल से बाहर हो गया। यह नतीजा केवल हार नहीं बल्कि विपक्ष की संगठनात्मक विफलता का प्रतीक बन गया। राजनीतिक तौर पर यह संदेश साफ है कि बिहार में विपक्ष न केवल बिखरा हुआ है बल्कि अपने ही विधायकों पर नियंत्रण खो चुका है। कांग्रेस में संभावित टूट और राजद के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आ चुका है। उधर, भाजपा शासित हरियाणा में दो सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को एक एक सीट मिली, लेकिन असली कहानी यहां भी अंदरखाने चली रणनीति की रही। भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया ने पहले वरीयता मतों में ही कोटा पार कर शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध की जीत जरूर हुई, लेकिन यह जीत बेहद संघर्षपूर्ण रही। कांग्रेस के चार वोट अमान्य हो गए और पांच वोट भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की ओर चले गए। यानी विपक्ष यहां भी पूरी तरह संगठित नहीं दिखा। यह नतीजा बताता है कि हरियाणा में भाजपा न केवल मजबूत स्थिति में है बल्कि विपक्ष के भीतर सेंध लगाने की क्षमता भी रखती है। कांग्रेस की जीत यहां राहत जरूर है, लेकिन अंदरूनी कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है कि राज्य में उसके 25 प्रतिशत विधायक अब उसके साथ नहीं हैं। वहीं ओडिशा में जो हुआ, वह विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। यहां भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। यह जीत सामान्य नहीं थी, बल्कि बड़े पैमाने पर हुई क्रॉस वोटिंग का नतीजा थी। बीजद और कांग्रेस के ग्यारह विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट किया, जिससे भाजपा को अप्रत्याशित बढ़त मिल गई। संख्या बल में पीछे होने के बावजूद भाजपा ने राजनीतिक प्रबंधन और संपर्क क्षमता के दम पर जीत हासिल की। यह परिणाम बताता है कि ओडिशा में भाजपा तेजी से मजबूत हो रही है और बीजद के लिए संघर्ष बढ़ गया है। विपक्षी एकता यहां पूरी तरह बिखरती नजर आई। उधर, अन्य राज्यों में देखें तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में कई उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ दलों और कांग्रेस के नेताओं ने बिना मुकाबले राज्यसभा में जगह बनाई। महाराष्ट्र में सातों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना भी राजनीतिक सहमति का उदाहरण रहा। हालांकि इन राज्यों में सीधा मुकाबला नहीं था, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि जहां भाजपा का सीधा प्रभाव नहीं है, वहां विपक्षी दल आपसी समझौते से काम चला रहे हैं। देखा जाये तो इन चुनावों के नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया है। भाजपा और एनडीए अब केवल चुनाव जीतने वाली मशीन नहीं रहे, बल्कि वे राजनीतिक रणनीति, विधायकों के प्रबंधन और अवसर को भुनाने में भी माहिर हो चुके हैं। दूसरी ओर विपक्ष की हालत बेहद कमजोर नजर आई। अपने ही विधायकों को एकजुट रखने में असफलता, क्रॉस वोटिंग, अनुपस्थिति और अंदरूनी कलह ने उनकी साख को गहरा नुकसान पहुंचाया है। बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में विपक्ष की हार केवल सीटों की हार नहीं है, बल्कि यह विश्वास की हार है। वहीं हरियाणा में भी विपक्ष की कमजोरी उजागर हुई। बहरहाल, राज्यसभा चुनावों ने साफ कर दिया है कि देश की राजनीति में फिलहाल एनडीए का दबदबा कायम है।

भाजपा ने यह दिखा दिया है कि वह हर स्तर पर राजनीतिक खेल को नियंत्रित करना जानती है। विपक्ष के लिए यह चेतावनी है कि अगर उसने अपने भीतर की कमजोरियों को दूर नहीं किया, तो आने वाले चुनावों में उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण और वह सम्मान के पात्र

संसदीय स्थिरता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सम्मान का पात्र है। 11 मार्च, 2026 को, अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव ध्वनि मत से पराजित हो गया, जो पिछले प्रयास के लगभग 4 दशक बाद किया गया था। 119 सांसदों द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ, विपक्ष ने अध्यक्ष के आचरण में कथित पक्षपात को उजागर किया। 543 सदस्यीय सदन में अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 272 वोटों की आवश्यकता होती है और ऐतिहासिक रूप से, आज तक किसी भी अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है। अध्यक्षों को दी जाने वाली बार-बार की चुनौतियां विधायिका में राजनीतिक तनाव को रेखांकित करती हैं, जो सत्ता संतुलन और कानून निर्माताओं के बीच आपसी सम्मान पर सवाल उठाती हैं। इस प्रकार, अध्यक्ष की भूमिका विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने, दोनों के लिए अनिवार्य है। असफल महाभियोग प्रस्ताव के बाद, अध्यक्ष बिरला ने अपनी निष्पक्षता दोहराई और जोर देकर कहा कि नियम प्रधानमंत्री सहित सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष के माइक्रोफोन को म्यूट करने का कोई तंत्र नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, ''यह सदन कोई मेला या उत्सव नहीं है। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, और किसी को भी उनके बाहर बोलने का अधिकार नहीं है, चाहे उनका पद कुछ भी हो।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष के अनियंत्रित प्रदर्शन की आलोचना की और राहुल गांधी की कम उपस्थिति पर प्रकाश डाला, जो कि 17वीं लोकसभा में 51 प्रतिशत और 16वीं लोकसभा में 52 प्रतिशत थी, जबकि औसत क्रमशः 66 प्रतिशत और 80 प्रतिशत रहा है। विपक्ष ने 'माफी मांगो' के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और गृह मंत्री से माफी की मांग की। महाभियोग प्रस्ताव ने सत्ताधारी दल के भारी बहुमत को रेखांकित और संसदीय प्रक्रियाओं के महत्व को सुदृढ़ किया। इसने उस सम्मान पर प्रकाश डाला, जो सदन अपनी विधायी प्रक्रियाओं के लिए चाहता है। भारत के संसदीय इतिहास में महाभियोग प्रस्ताव दुर्लभ घटनाएं हैं। अध्यक्ष बिरला को हटाने का प्रयास ऐसा चौथा प्रयास है, जो इस महत्वपूर्ण पद की अंतर्निहित चुनौतियों को रेखांकित करता है। अध्यक्ष का पद राष्ट्रपति की बजाय स्वयं सदन द्वारा सुरक्षित होता है और निष्कासन केवल बहुमत के वोट से ही हो सकता है। यह कार्यालय की स्वतंत्रता और संसदीय स्थिरता बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। पिछले प्रयासों में, 1954 में पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव और बिरला के खिलाफ हालिया प्रस्ताव शामिल हैं। ये घटनाएं पक्षपात और संसदीय आचरण के संबंध में चल रही चिंताओं को उजागर करती हैं। स्वतंत्रता के बाद से, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के 3 असफल प्रयास हुए हैं। पहला 1954 में पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के खिलाफ था। प्रस्ताव पर 18 दिसम्बर को चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और विपक्ष के नेता ए.के. गोपालन ने भाग लिया। सांसदों ने मावलंकर पर प्रासंगिक प्रश्नों को अस्वीकार करने और स्थगन नोटिसों को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया था। 1966 में, सांसदों ने सरदार हुकम सिंह पर उन सांसदों में बाधा डालने का आरोप लगाया, जो सरकार को शर्मिंदा कर सकते थे और विशेषाधिकार नोटिस प्रस्तुत करने में विफल रहने का आरोप लगाया। प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि 50 से कम सांसदों ने इसका समर्थन किया था। सी.पी.एम. (माकपा) सांसद सोमनाथ चटर्जी ने अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। प्रमुख प्रतिपक्षियों में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पी. चिदम्बरम शामिल थे। सदन ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। राज्यसभा में, 2024 में उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के प्रयास विफल रहे हैं। इसी तरह, 2020 में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को हटाने के नोटिसों पर बहस नहीं हो सकी। 'प्रभावी बहुमत' की आवश्यकता, जिसे सदन के सभी मौजूदा सदस्यों के बहुमत के रूप में परिभाषित किया गया है, अध्यक्ष को हटाने की सीमा निर्धारित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एक महत्वपूर्ण आम सहमति आवश्यक है। महाभियोग बहस के दौरान, विपक्षी नेताओं ने उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, दोषपूर्ण माइक्रोफोन, विपक्षी सदस्यों के लिए सीमित बोलने के अधिकार और सामूहिक निलंबन के बारे में चिंताएं उठाईं। ये मुद्दे संसदीय संस्थाओं और अध्यक्ष के कार्यालय के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वह संसदीय मंचों में शामिल होने की बजाय पार्टी के उद्देश्यों और प्रचार के लिए यात्रा करते हैं। शाह ने कहा, ''उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण, बजट और अनुच्छेद 370 पर चर्चा को छोड़ दिया। प्रमुख संसदीय सत्रों के दौरान, वह विदेश यात्रा करते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है।'' उन्होंने आगे कहा, ''इस सदन के स्थापित इतिहास के अनुसार, इसकी कार्यवाही आपसी विश्वास के आधार पर संचालित होती है। अध्यक्ष एक तटस्थ संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। संसदीय राजनीति के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया।''

सम्पादकीय...

इच्छा मृत्यु.....

हाल ही में हरीश राणा नाम के 31 वर्षीय युवक के माता-पिता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। ऐसा देश में पहली बार हुआ। निर्णय देते वक्त अदालत बहुत भावुक भी हो गई। इस युवक के माता-पिता को सैल्यूट भी किया। 13 साल से यह युवक कोमा में था। उसके पूरे शरीर को लकवा भी मार गया था। उसके ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी लेकिन माता-पिता और छोटे भाई ने उसकी बहुत सेवा की। उन माता-पिता की हालत सोचकर कलेजा मुंह को आता है, जिन्हें अपने बेटे की मृत्यु की इजाजत अदालत से लेनी पड़ी। पिता ने कहा कि उसका बेटा टॉपर था। न जाने उसके कितने सपने थे। हॉस्टल में चौथी मंजिल से गिरा, तो फिर कभी उठ नहीं सका। मां सिसकते हुए बोली कि हमारे बाद उसकी देखभाल कौन करता, इसलिए ऐसा निर्णय लेना पड़ा। अर्से से अपने यहां इच्छा मृत्यु पर बहस चल रही है। मुम्बई की नर्स अरुणा शानबाग भी दशकों तक कोमा में रहीं। उनके लिए भी इच्छा मृत्यु की मांग अदालत से की गई थी लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। बाद में निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई। जिस परिवार पर ऐसी आफत टूटती है, उनके दुखों के बारे में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस मामले में अदालत ने भी कहा कि सरकार को इस बारे में कानून बनाना चाहिए। कुछ साल पहले अंग्रेजी के एक अखबार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती ऐसे मरीजों के बारे में एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें बताया गया था कि कई ब्रेन डेड मरीज वहां सालों से भर्ती हैं। घर वालों से अस्पताल कहता है कि अब उन्हें घर ले जाएं, जिससे कि अन्य मरीजों को उनके बेड मिल सकें। लेकिन घर वाले इसके लिए तैयार नहीं होते। उन्हें लगता है कि घर ले जाकर वे मरीजों की 24 घंटे देखभाल कैसे करेंगे। अस्पतालों की मजबूरी यह होती है कि उनके पास सीमित संसाधन होते हैं, एक बेड खाली हो, तो हो सकता है कि अनेक मरीज उस लाइन में लगे हों। यूं भी अपने देश में अस्पतालों की भारी कमी है। प्राइवेट सैक्टर अस्पतालों में जाने के बारे में साधनहीन मरीज तो सोच भी नहीं सकते। शिक्षा की तरह इलाज भी मनुष्य के मौलिक अधिकारों में एक होना चाहिए लेकिन शायद ही कोई इसके बारे में सोचता हो। इसके अलावा ज्यों-ज्यों चिकित्सा प्राइवेट सैक्टर के हाथों में गई है, इलाज महंगे से महंगा होता गया है। लोगों के सारे संसाधन किसी एक व्यक्ति के इलाज में लग जाते हैं। फिर भी बहुत बार मरीज ठीक नहीं होता। हरीश राणा के परिवार को भी उसके घर में रहने पर भी इलाज के लिए अपना तीन मंजिला मकान तक बेचना पड़ा था। उसके माता-पिता ने यह भी कहा कि अदालत के इस फैसले से उन जैसे अनेक परिवारों को राहत मिलेगी, जो इस तरह की विपत्ति से गुजर रहे हैं। वे वर्षों से बेटे को इस असहाय अवस्था में देख रहे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। पश्चिम के कई देशों में इच्छा मृत्यु वैध है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आस्ट्रेलिया के 100 वर्षीय एक वैज्ञानिक इसके लिए स्विट्जरलैंड गए थे।

भाजपा की चुनावी मशीन को कैसे आकार देती है मोदी-शाह की सांझेदारी

जैसा कि अब कई राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम यह जानते और महसूस करते हैं कि सफलता शायद ही कभी अचानक मिली प्रेरणा से आती है। यह आमतौर पर योजना, अनुशासन और टीम वर्क से आती है। पिछले एक दशक में, भारतीय राजनीति ने एक अनूठी सांझेदारी देखी है, जिसे अक्सर आधुनिक भारत के सबसे प्रभावी राजनीतिक संयोजनों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है- नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच का कामकाजी रिश्ता। उनकी राजनीतिक शैली आखिरी समय के फैसलों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नहीं टिकी। इसकी बजाय, यह तैयारी, समन्वय और चुनावों के लगभग कॉर्पोरेट-शैली के प्रबंधन पर आधारित है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो पार्टी अचानक प्रचार के लिए नहीं जागती। मोदी और शाह के बीच की समझ नई नहीं है। उनकी राजनीतिक सांझेदारी गुजरात में साथ काम करने के समय से कई साल पुरानी है। उन वर्षों के दौरान, उन्होंने काम करने की एक ऐसी शैली विकसित की, जहां भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं लेकिन संचार निरंतर बना रहता था। नरेंद्र मोदी को व्यापक रूप से चेहरे, संचारक और उस नेता के रूप में देखा जाता है, जो बड़े राष्ट्रीय संदेश को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी ओर, अमित शाह को अक्सर रणनीतिकार के रूप में वर्णित किया जाता है, वह व्यक्ति, जो राजनीतिक युद्धक्षेत्र का सूक्ष्म विवरण के साथ अध्ययन करता है। जिम्मेदारियों का यह विभाजन एक सुचारू प्रणाली बनाता है। एक व्यक्ति विजन और संदेश पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि दूसरा संगठन और कार्यान्वयन पर। राजनीतिक हलकों में लोग अक्सर कहते हैं कि मोदी राष्ट्र से बात करते हैं, जबकि शाह पार्टी से। भाजपा के चुनाव प्रबंधन का चौंकाने वाला पहलू यह है कि तैयारी कितनी जल्दी शुरू हो जाती है। जब किसी राज्य में चुनाव की उम्मीद होती है, तो जमीनी काम आमतौर पर कम से कम 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। उस समय तक, सर्वेक्षण किए जा चुके होते हैं, स्थानीय नेताओं का आकलन किया जा चुका होता है और निर्वाचन क्षेत्र स्तर का डाटा केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचना शुरू हो जाता है। अमित शाह विस्तृत जानकारी पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार किस बूथ पर प्रदर्शन खराब रहा? कौन-सा स्थानीय मुद्दा मतदाताओं को परेशान कर रहा है? कौन-सा समुदाय उपेक्षित महसूस कर रहा है? ये सवाल चुनाव से एक हफ्ते पहले नहीं पूछे जाते, ये महीनों पहले पूछे जाते हैं। इन विवरणों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के लिए टीमें बनाई जाती हैं। बूथ स्तर की समितियां सक्रिय की जाती हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाता है और धीरे-धीरे, पूरे राज्य में राजनीतिक गतिविधियों का एक नैटवर्क फैलने लगता है। जब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, तब तक अधिकांश जमीनी काम पहले ही पूरा हो चुका होता है।

बूथ-स्तर पर ध्यान - भाजपा संगठन के भीतर सबसे अधिक दोहराए जाने वाले वाक्यांशों में से एक 'बूथ प्रबंधन' है। विचार सरल है-चुनाव अंततः व्यक्तिगत मतदान केंद्रों के स्तर पर तय होते हैं। अमित शाह की संगठनात्मक शैली के तहत, पार्टी अक्सर प्रत्येक बूथ की जिम्मेदारी विशिष्ट कार्यकर्त्ताओं को सौंपती है। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं से संपर्क किया जाए, स्थानीय चिंताओं को समझा जाए और पार्टी का संदेश हर घर तक पहुंचे। हालांकि यह सुनने में सरल लग सकता है लेकिन इसके लिए भारी समन्वय की आवश्यकता होती है। सूचियां तैयार की जाती हैं, बैठकें आयोजित की जाती हैं और संचार केंद्रीय नेतृत्व से लेकर पार्टी की सबसे छोटी इकाइयों तक प्रवाहित होता है। इस तरह का अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि जब अभियान अपने चरम पर पहुंचे, तो ढांचा पहले से ही मजबूत हो। मोदी की भूमिका -जहां संगठनात्मक ढांचा पृष्ठभूमि में चुपचाप काम करता है, नरेंद्र मोदी अभियान को सार्वजनिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनकी रैलियां अक्सर बड़े आयोजन बन जाती हैं, जो भारी भीड़ और व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित करती हैं। लेकिन प्रत्येक रैली के पीछे सावधानीपूर्वक योजना होती है। स्थानों का चयन रणनीतिक रूप से किया जाता है। विषयों का चयन उस विशेष क्षेत्र की चिंताओं के आधार पर किया जाता है। यहां तक कि दौरों का समय भी अधिकतम राजनीतिक प्रभाव पैदा करने के लिए तय किया जाता है। कई मायनों में, मोदी के भाषण अभियान को भावनात्मक और प्रेरक परत प्रदान करते हैं। इस नेतृत्व शैली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता पार्टी कार्यकर्त्ताओं के साथ नियमित बातचीत है। बैठकें बार-बार आयोजित की जाती हैं- कभी भौतिक, कभी आभासी, जहां जमीनी स्तर के नेताओं से फीडबैक एकत्र किया जाता है। यह एक दोतरफा प्रणाली बनाता है। केंद्रीय नेतृत्व निर्देश देता है लेकिन वह जिला नेताओं और बूथ स्तर के कार्यकर्त्ताओं की रिपोर्ट भी सुनता है। उम्मीदवारों का सावधानीपूर्वक चयन - उम्मीदवार चयन एक और क्षेत्र है, जहां मोदी-शाह शैली दिखाई देती है। केवल वरिष्ठता या लोकप्रियता पर भरोसा करने की बजाय, कई कारकों का अध्ययन किया जाता है। सर्वेक्षण, स्थानीय फीडबैक, प्रदर्शन रिकॉर्ड और जनता की धारणा, सभी इसमें भूमिका निभाते हैं। कभी-कभी इससे चौंकाने वाले फैसले भी होते हैं। मौजूदा विधायकों को बदला जा सकता है, यदि पार्टी को लगता है कि कोई नया चेहरा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। उनकी रणनीति का एक और तत्व निरंतर सीखना है। प्रत्येक चुनाव के बाद, चाहे जीत हो या हार, पार्टी आंतरिक समीक्षा करती है। डाटा का विश्लेषण किया जाता है, गलतियों की पहचान की जाती है और भविष्य के लिए रणनीतियां समायोजित की जाती हैं। अनुशासन की संस्कृति - शायद मोदी-शाह सांझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पार्टी के भीतर अनुशासन की संस्कृति है। कार्यकर्त्ता समझते हैं कि अभियान कोई अनियमित घटनाएं नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक नियोजित ऑपरेशन हैं। हर स्तर के नेताओं से समय सीमा का पालन करने, बैठकों में शामिल होने और सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। यह अनुशासित दृष्टिकोण पार्टी को दिशा और गति का अहसास कराता है। चाहे कोई भाजपा का समर्थन करे या नहीं, कई राजनीतिक पर्यवेक्षक एक बात पर सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सांझेदारी ने भारत में चुनाव आयोजित करने के तरीके को बदल दिया है। उनकी पद्धति दिखाती है कि राजनीतिक सफलता केवल भाषणों या नारों के बारे में नहीं है, यह योजना, टीम वर्क और उस क्षण से महीनों, कभी-कभी सालों पहले काम करने की क्षमता के बारे में भी है, जब मतदाता अंततः पोलिंग बूथ में कदम रखते हैं। और आधुनिक राजनीति में, यही तैयारी सारा अंतर पैदा कर सकती है, जिसे दुर्भाग्य से हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से भूल और छोड़ चुकी है। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भाजपा के भविष्य की पार्टी बने रहने की अधिक संभावना है।

-देवी एम. चेरियन

राजनीतिक जंग के आगाज में लोकतांत्रिक मूल्य फिर दांव पर

ललित गर्ग।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र की परिपक्वता, जनविश्वास और राजनीतिक संस्कृति की परीक्षा भी होते हैं। जब किसी राज्य या क्षेत्र में चुनाव की घोषणा होती है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता है और दल अपने-अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं। किंतु इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक संस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है-भारत का चुनाव आयोग। यही संस्था सुनिश्चित करती है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त वातावरण में संपन्न हों। इस बार असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे चार बड़े राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही देश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन पांचों स्थानों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और देश के 17.4 करोड़ मतदाताओं के मन एवं मानसिकता की जानकारी भी मिलेगी। पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान कम चरणों में संपन्न कराया जा रहा है, जो प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा सकता है। असम, केरल और पुडुचेरी में जहां 9 अप्रैल को मतदान प्रस्तावित है, वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं-पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। इन चुनावों की ओर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि इनके परिणाम केवल इन राज्यों की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन चुनावों का महत्व केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य की भी परीक्षा है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष और टकराव की स्थिति देखने को मिलती रही है। वहां सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार चुनावी हिंसा और राजनीतिक तनाव की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। इसलिए यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि यह भी एक कसौटी है कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया हिंसा और भय से मुक्त रहकर संपन्न हो सकती है। लोकतंत्र का मूल आधार यह है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी दबाव, भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में इस आदर्श को बनाए रखना आसान नहीं है। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। इसके लिए आयोग को सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की सुरक्षा और मतदाता सूची की शुद्धता जैसे अनेक पहलुओं पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के आचरण पर भी नजर रखना जरूरी होता है ताकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो। इन चुनावों के संदर्भ में पश्चिम बंगाल विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। लंबे समय से वहां राजनीतिक हिंसा और टकराव की घटनाएं सामने आती रही हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस बार वहां सत्ता परिवर्तन की संभावना के कारण राजनीतिक संघर्ष और तीखा हो सकता है। सत्तारूढ़ नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली ममता बनर्जी की सरकार के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है, वहीं विपक्ष अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस परिस्थिति में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखे। दूसरी ओर केरल और तमिलनाडु की राजनीति भी अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण चर्चा में रहती है। केरल में आमतौर पर सत्ता दो प्रमुख राजनीतिक मोर्चों के बीच बदलती रही है, जबकि तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के लिए जानी जाती है। इन राज्यों में चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है, किंतु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान की परंपरा भी देखने को मिलती है। असम की स्थिति भी अलग है, जहां पूर्वोत्तर भारत की राजनीति के संदर्भ में चुनाव के परिणाम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि वहां सत्तारूढ़ दल फिर से सत्ता में लौटता है तो यह क्षेत्रीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाएगा। हालांकि इन सभी चुनावों के संदर्भ में एक प्रश्न लगातार उठता है कि क्या राजनीतिक दल लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं। चुनावी राजनीति में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, किंतु जब वह प्रतिस्पर्धा हिंसा, घृणा और असहिष्णुता में बदल जाती है तो लोकतंत्र की मूल भावना को चोट पहुंचती है। दुर्भाग्य से कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीतने की होड़ में लोकतांत्रिक शालीनता को नजरअंदाज कर देते हैं। आरोप-प्रत्यारोप, व्यक्तिगत हमले और हिंसक घटनाएं इस प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। इस स्थिति में यह केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं रह जाती कि वह चुनाव को निष्पक्ष बनाए। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वे लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखें। यदि दल स्वयं ही आचार संहिता का सम्मान करें और अपने कार्यकर्ताओं को संयमित आचरण के लिए प्रेरित करें तो चुनावी प्रक्रिया कहीं अधिक स्वस्थ और सकारात्मक बन सकती है। लोकतंत्र की सफलता केवल संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक चेतना पर भी निर्भर करती है। इसके साथ ही मतदाताओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। यदि मतदाता जागरूक और सजग हों तो वे ऐसे नेताओं और दलों को प्रोत्साहित करेंगे जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। मतदाताओं को यह समझना होगा कि उनका वोट केवल एक राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा तय करने वाला निर्णय भी है। इन पांच क्षेत्रों में होने वाले चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे यह संदेश देंगे कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि ये चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होते हैं तो यह न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण होगा। भारत को अक्सर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है, इसलिए यहां होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रहती है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है, बल्कि वे लोकतंत्र के मूल्यों की परीक्षा भी हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि इन चुनावों में राजनीतिक दल संयम और जिम्मेदारी का परिचय दें, चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता और दृढ़ता बनाए रखे तथा मतदाता जागरूकता के साथ मतदान करें, तो यह लोकतंत्र की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करेगा। प्रश्न यह है कि क्या हम इन चुनावों के माध्यम से एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे, जिसमें लोकतंत्र केवल मतपेटियों तक सीमित न रहकर शालीनता, सहिष्णुता और जनविश्वास की भावना को भी मजबूत करे। यही वह कसौटी है जिस पर इन चुनावों की सफलता या असफलता का वास्तविक मूल्यांकन किया जाएगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वरुण ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

टीएमयू में खूब गुदगुदा गए हास्य-व्यंग्य के कवि शैलेश लोढ़ा

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कवि सम्मेलन के नायक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता फेम रहे शैलेश लोढ़ा अपनी अनूठी प्रस्तुति और हास्य-व्यंग्य से मेहमानों और हजारों-हजार स्टुडेंट्स को खूब गुदगुदाया। व्यंग्यकार गोविंद राठी ने समाज की विसंगतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए अपने शब्दों से सर्जरी की मानिंद काम किया। वीर रस के कवि अशोक चारण की प्रभावी आवाज, अदायगी, त्वरित हास्य बोध से खूब वाहवाही लूटी। चारण ने जोशीली कविताओं के जरिए देशभक्ति की अलख जगा दी। हास्य कवि चेतन चर्चित ने जहां हंसी के ठहाकों से गुदगुदाया, वहीं अपनी रचनाओं से समाज को गहरा संदेश भी दे गए। श्रृंगार रस की कवयित्री मनु वैशाली के प्रेम गीतों पर पूरा पंडाल झूमता नज़र आया। गीतकार अभिसार गीता शुक्ल ने प्रेम और विरह की रचनाओं से देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। कुलाधिपति सुरेश जैन के संग-संग मेहमान कवियों, जीवीसी मनीष जैन, एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन, अनिल जैन आदि की इस मौके पर उल्लेखनीय मौजूदगी रही। संचालन की कमान व्यंग्यकार गोविंद राठी ने संभाली तो अध्यक्षता शैलेश लोढ़ा ने की। शैलेश लोढ़ा ने भारत की बढ़ी आबादी की कहानी पर केंद्रित अपनी कविता- जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है... को कुछ इस तरह बयां किया- बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा,बीबी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने आखिर वही तो हैं अपनेभले ही हर दिन बोझ हो, और खुद पर उधार हैतू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। श्रृंगार रस की कवयित्री मनु वैशाली ने मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए कवि सम्मेलन का आगाज़ किया- मात वीणा वादिनी इतना अगर कर देमैं रहूं या न रहूं मेरा देश अमर कर दे । भीड़ से गदगद श्रोताओं के सम्मान में कहा-सकल संसार के विस्तार से सजाकर रखा है। हमारी कल्पनाओं से बहुत अच्छा बनाकर रखा है। जमाना घूम आए हम मगर देखा नहीं ऐसा,खुदा कुछ नहीं बना पाया, बनाकर तुमको ऐसा लगता है। उन्होंने जैसे ही अपनी चर्चित कविता मोहिनी सुनाई तो पंडाल तालियों से गूज उठा। उंगली लपेट लट कर अटखेलियां तो,रुप से रति के जीत करे मोहिनीचटकीली चितवन चंलला चकोरी कि चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी शौर्य गाथाओं के कलमकार अशोक चारण ने कहा,जित्रा के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में,हाथों में अगर तिरंगा नहीं लेते। अब्बा ने तुम्हारे बताया नहीं शायद तुम्हें,बाप, बाप होता है, बाप से कभी पंगा नहीं लेते। अंत में उन्होंने वीर रस की कविता- मेरी मौत को मिले तिरंगा मर कर भी जी जाऊंगा सुनाकर श्रोताओं में जोश भर दिया। व्यंग्यकार गोविन्द राठी ने पेड़ और उल्लू की पैरॉडी से राजनीति पर करारा कटाक्ष किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी रचना- श्मशानघाट का उद्घाटन के जरिए बीवीआईपी कल्चर, राजनीति और रीति-रिवाजों पर भी जमकर तीखी चोट की। मां की महिमा का उन्होंने बखान यूं किया- बस एक मां की मुहब्बत दिखाई देती है।कायनात में एक ही हूर दिखाई देती है। बूढी मां तेरी झुर्रियों की कसम,हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। कवि सम्मेलन में कुलाधिपति परिवार से फर्स्ट लेडी वीना जैन, ऋचा जैन, जहान्वी जैन, नंदिनी जैन, वीसी प्रो. बीके जैन, सीओ हाईवे राजेश कुमार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनन्द मोहन गुप्ता, अनिल अग्रवाल, राजेश रस्तोगी के अलावा टीएमयू परिवार से अभिषेक कपूर, प्रो. हरबंश दीक्षित, प्रो. एमपी सिंह, प्रो. आरके द्विवेदी, मनोज जैन, प्रो. विपिन जैन, डॉ. विपिन जैन, डॉ. रवि जैन आदि की भी गरिमामयी मौजूदगी रही।

भाजपा कार्यालय हुआ भजन एवं सुंदरकाड़ का पाठ

मुरादाबाद। चैत्र नवरात्रि शुभारंभ से पूर्व आज भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के नेतृत्व में बुद्धि विहार कार्यालय पर भजन एवं भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बालाजी संस्कीर्तन मंडल के मोहन कपूर एवं अर्चना कपूर के द्वारा सर्वप्रथम पूजा अर्चना कर भजनों की श्रृंखला प्रस्तुत करने के उपरांत सुंदरकांड पाठ का बड़े ही भव्य एवं विस्तार से वर्णन किया गया सभी भक्तगण ताली बजाते बजाते प्रभु की भक्ति में रंग गये सारा वातावरण प्रभुमय हो गया। सुंदरकांड पाठ के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया सभी भक्तों ने प्रसाद का आनंद लिया । भजन प्रस्तुति एवं सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम श्रोतागणों में क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, कार्यक्रम संयोजक एवं महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला सुनीता भंडूला,जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल नगर विधायक रितेश गुप्ता महापौर विनोद अग्रवाल एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त एमएलसी गोपाल अंजान पूर्व सांसद वीर सिंह महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ.शैफाली सिंह,गौ सेवा आयोग का सदस्य दीपक गोयल,राजू कलरा, संतोष सिंह, मनीष सिंह,साध्वी गीता प्रधान, प्रांतीय परिषद सदस्य निमित जयसवाल महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता अर्चित गुप्ता महानगर महामंत्री विशाल त्यागी शम्मी भटनागर अमित शर्मा,महानगर उपाध्यक्ष नवदीप टंडन हेमराज सैनी अशोक सैनी गेत्र पाल सिंह मंगल सेन राजपूत कपिल देव जाटव, महानगर मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित सुनीता शर्मा वनिता मल्होत्रा सिमरन कौर अभिषेक चौबे दीपक चौधरी मनीष गुज्जर, दीपक बाबू सीए महेंद्र सिंह बब्बू नत्थूराम दिनेश शीर्षवाल राहुल सेठी,राजेंद्र अग्रवाल,दिनेश सिसोदिया,चंद्र प्रजापति अजय वर्मा सर्वेश पटेल,रूचि चौधरी शशी किरण सुनीता सैनी,शीतल कुमारी, हेमा खत्री,मदालसा शर्मा,कविता गुप्ता, राधा रानी,पूनम सैनी गौरव श्रीवास्तव, सुरेंद्र बिश्नोई ,कुलदीप नारायण, अभिषेक राठौर,योगेंद्र रस्तोगी, अरविंद सिंह अमित सिंह, विपिन प्रजापति राजीव शर्मा ,विशाल रस्तोगी,कपिल गुप्ता, सोमपाल सिंह, सूर्य मोहन शमशेरी, मिथुन शर्मा संजीव चौहान,सिद्धार्थ शर्मा,हरीश प्रजापति,दिनेश शुक्ला, हरिओम सैनी, सौरभ सक्सैना सुमित चौहान, गुड्डू सिंह,जगदीश कश्यप, अमित कुमार गुप्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा,राजीव गोस्वामी आदि शामिल रहे।

कांग्रेस का प्रोग्राम- विकास भवन को घेरकर मांगा मनरेगा भुगतान

फतेहपुर।

मंगलवार को कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरों व रोजगार सेवकों के पिछले 8 माह के लंबित भुगतान तथा गैस सिलेंडर के बढ़े दाम कम करने के लिए कलेक्ट्रेट से नारेबाजी करते हुए पहुंचे और विकास भवन का घेराव किया। जिला व शहर कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कहा कि गरीब मजदूरों के मुँह से निवाला छीनने वाली भाजपा सरकार ने लगभग एक करोड़ मनरेगा मजदूरों का पिछले 75 दिनों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया, जिससे उनको परिवार पालना दुश्वार हो रहा है साथ ही लगभग 40 हजार रोजगार सेवकों व सांविदा कर्मियों का पिछले 8 माह से भुगतान नहीं किया गया। शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डू ने कहा कि जहां एक ओर देश मंहगाई व बेरोजगारी से जूझ रहा है वही गरीब से काम कराकर उसका भुगतान न करना भुखमरी को बढ़ावा देना है साथ ही गैस सिलेंडर में अकस्मात् 60 रुपए की बढ़ोत्तरी कर गरीब जनता के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। कहा कि आज पूरा विश्व भारत देश के ऊपर हँस रहा है एवं ऐसा प्रतीत होता

कलेक्ट्रेट से नारे लगाते हुए किया प्रदर्शन

है कि यह नेहरू व इंदिरा का भारत नहीं बल्कि एक निरीह भारत है। जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रदर्शन में मुख्यरूप से, महिला नेता सन्तोष कुमारी शुक्ला एडवोकेट, शकीला बानो, कलीम उल्ला सिद्दीकी, कल्याण सिंह, रंजीत मौर्य, आशीष गौड़ एडवोकेट, इं. देवी प्रकाश दुबे, आरिफ खान, आदित्य श्रीवास्तव, पंडित राम नरेश महराज, चौधरी मोईन राईन, प्रशांत शुक्ला, मोहित मिश्रा, कल्लू कोरी, अंकुर अवस्थी, सैयद शहाब अली, राम चंद्र शुक्ला, निजामुद्दीन, मनोज गुप्ता घायल, सरदार नरेंद्र सिंह रिंकी, जगतपाल पासवान, राम करण शर्मा, एम एल श्रीवास, नौशाद अहमद, सुधीश पाण्डेय, बसीर अहमद, आनंद सिंह गौतम, राजीव श्रीवास्तव, उस्मान, रमजान, अमित श्रीवास्तव, रिजवान, फारूक, आदर्श शुक्ला, अजय बच्चा,पप्पी राजपूत, हम्माद हुसैन, अकरम काले आदि कांग्रेसी उपस्थित रहे।

एक्टिव प्रेस क्लब के रोज़ा इफ्तार में जुटी शख्सियतें

मुरादाबाद।

एक्टिव प्रेस क्लब मुरादाबाद द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पवित्र रमजान माह के अवसर पर रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों तथा विभिन्न धर्मों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का परिचय दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में प्रेम, एकता और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना रहा। इफ्तार से पूर्व सभी ने मुल्क में अमन-चैन और तरक्की के लिए दुआ की। इफ्तार के दौरान मौजूद लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा खोला और आपसी मेल-मिलाप का संदेश दिया। इस अवसर पर एक्टिव प्रेस क्लब के महासचिव हाजी अशरफ अली ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि क्लब हर वर्ष रमजान में इफ्तार का आयोजन करता है, जिससे समाज में भाईचारा मजबूत होता है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया। एक्टिव प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने सभी मेहमानों, विशेष रूप से रोजेदारों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों में निकटता बढ़ाते हैं।

इफ्तार में शामिल हुए सभी धर्मों के लोग

उन्होंने कहा कि हाजी अशरफ अली द्वारा लगाया गया यह पौधा आज वटवृक्ष बन चुका है। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग योगेश कुमार, पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन,पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी,हाजी जुनैद इकराम कांग्रेस महानगर अध्यक्ष,इरशाद सैफी एड,डॉक्टर मो खालिद,मो मोअज़्ज़म,बार अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एड,सौलत अली एड,,मोहम्मद इकबाल, कुमार देव, नायब इमाम मुफ्ती सैय्यद फहद अली, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर, मोज़्ज़म अली, रेहान अहमद, हाजी बोस, मोहम्मद फहीम, मनमोहन सैनी, सुनील कुमार शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, परवेज नाज़िम, जाकिर अली बेग, बिलाल अहमद, मोहम्मद जान तुर्की, नाजिम मंसूरी, तमीम अहमद नसीमी, अब्दुल करीम फारूखी उर्फ करीमा, मोहम्मद अनवर 'भूरे', मोहम्मद अहमद (काजीपुरा), कौसर अली, गोविन्द पाल, साजिद वारसी, फज़ील अहमद, नदीम खान, अतहर हुसैन अंसारी, हम्माद हाशिर, आसिफ अली, आरिफ अली, राजेश रस्तौगी, जव्वाद अली, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी, मज़ाहिर खान आदि मौजूद रहें।

फर्म मालिक के अपहरण की योजना बना रहे पांच बदमाश दबोचे

मुरादाबाद। मैनाठेर क्षेत्र में फर्म मालिक के अपहरण की योजना बना रहे पांच बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पिस्टल, तमंचा और फर्जी नंबर प्लेट लगी एक कार बरामद की है। शहर के करुला निवासी याहया की मैनाठेर में डिजाइन वर्ल्ड आइएनसी नाम से फर्म है। फर्म में काम करने वाले इमरान निवासी पंडित नगला ने अपने साथी सारिक उर्फ लाला निवासी जयंतीपुर मझोला, जाने आलम निवासी काली मंदिर के पास मझोला, रिजवान उर्फ बड़ा निवासी मुगलपुरा, इमरान निवासी सिविल लाइंस के साथ मिलकर फर्म मालिक का अपहरण करने की योजना बना ली।इन्हें जानकारी हुई की फर्म मालिक सोमवार की देर रात फर्म से वापस घर लौट रहे हैं। पांचों बदमाश उनका अपहरण करने के लिए फरीदपुर अंडरपास के पास पहुंच गए। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस और एसओजी टीम को लगी तो घेराबंदी कर पांचों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है।

नाबालिग पुत्री की बरामदगी व भूमि बचाने के लिए धरने पर बैठे पीड़ित

फतेहपुर।

मंगलवार को 2 पीड़ित महिलाओं ने कई अन्य लोगों के साथ कलेक्ट्रेट में धरना दिया। ग्राम घोषिन का पुरवा मजरे खरगूपुर थाना सुल्तानपुर घोष निवासिनी पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी लगभग 17 वर्षीय पुत्री कु0 पासवान को 3 नवम्बर 2025 की रात गांव के सुशील यादव, सुधीर यादव व बबलू घोषी भगा ले गये हैं। 5 नवम्बर 2025 को सुल्तानपुर घोष थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। आरोपियों द्वारा उसे बराबर धमकाया जा रहा है। उसने बताया कि अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आये थे। उनसे भी न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित माँ की मांग है कि उसकी नाबालिग पुत्री की बरामदगी कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। वहीं ग्राम टेनी परगना हथगाम, तहसील खागा निवासिनी विधवा महिला सुनीता देवी ने बताया कि उसकी भूमिधरी भूमि गाटा संख्या 24, की खाता संख्या 441 की नाप कराकर उसे कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। उसकी भूमि हाईवे से टेनी मार्ग पर स्थित है, जिस पर मदन उर्फ राजकुमार केशरवानी ने कब्जा कर रखा है। बताया कि न्याय की गुहार लगा-लगाकर थक गई है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाकायदा बैनर लगाकर इनके साथ दयाशंकर, संतलाल, रामराज, राजेंद्र प्रसाद हंस, दयाराम, रामबाबू, कमलेश, पप्पू सोनकर, रामपति वास शीतल प्रसाद आदि भी अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना स्थल पर आकर शिकायती पत्र लिया और समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया। धरने पर बैठे पीड़ितों को देखकर लोग आपस में सवाल उठाते रहे कि आखिर सत्तापक्ष और विपक्ष का क्या काम है। आम जनता को दर-दर क्यों भटकना पड़ता है। उसे अपने गांव से लेकर मुख्यालय तक की परेड क्यों करनी पड़ती है ? पीड़ित की सुनवाई और उसकी समस्याओं का निदान समय रहते

स्थानीय स्तर पर नहीं हुई सुनवाई तो आ गये मुख्यालय न्याय के लिए कितनी बार और कहां-कहां लगाएं गुहार कांग्रेसी भी देखकर गुजरते रहे नहीं बने पीड़ितों की आवाज़ पीड़ित माँ सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी लगा चुकी है गुहार लोगों में रही चर्चा-सबको अपनी-अपनी राजनीति की चिन्ता, न्याय का पक्षधर कौन ?

क्यों नहीं कराया जाता ? जबकि ऐसा नहीं है कि आम लोग ही देखते रहे, कांग्रेसियों का विकास भवन घेराव का कार्यक्रम था। कांग्रेसी भी धरने पर बैठी पीड़ित महिला, बच्चों व आदमियों को देखते हुए गुजरे। लेकिन उनकी आवाज़ बनना शायद मुनासिब नहीं समझा। क्या वास्तव में सबको सिर्फ अपनी-अपनी राजनीति की चिन्ता है, तो फिर न्याय का पक्षधर कौन है ?

अफवाहों से बचें; घबराएं नहीं, घर पर ही मिलेगा सिलिंडर, सरकार की एलपीजी प्रयोग में किफायत बरतने की अपील

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रमों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पैदा हुई चिंताओं के बीच, भारत के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऊर्जा सुरक्षा पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान में देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हालांकि, सरकार ने देश में आम लोगों से एलपीजी के मसले पर अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वे घबराएं नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने दावा किया है लोग पैनिक न करें। बुकिंग के बाद उनके घर पर ही मिलेगा सिलिंडर की डिलिवरी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे एलपीजी के इस्तेमाल में किफायत बरतने की कोशिश करें और संभव तो हो पीएनजी का इस्तेमाल शुरू करें। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला, नागरिकों की सुरक्षा और बाजार स्थिरता को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। एक तरफ जहां विदेश मंत्रालय वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है, वहीं पेट्रोलियम और शिपिंग मंत्रालयों ने घरेलू स्तर पर ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स के सुचारू संचालन का भरोसा दिया है। आपूर्ति को बाधित करने वाले तत्वों पर भी देशव्यापी कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऊर्जा आपूर्ति और कूटनीतिक पहल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

प्राकृतिक गैस की खपत को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों के तहत कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं का पीएनजी में शिफ्ट होना अधिक फायदेमंद होगा।

एलपीजी जमाखोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

एलपीजी जमाखोरों पर देशव्यापी कार्रवाई बाजार में ईंधन की कृत्रिम कमी रोकने के लिए सरकार ने प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है। सुजाता शर्मा के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में देश भर में लगभग 12,000 छापेमारी की गई है, जिनमें 15,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश- दिल्ली में एक दिन पहले 600 सिलेंडर जब्त किए गए, जबकि यूपी में 450 निरीक्षणों के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

जम्मू-कश्मीर और केरल- जम्मू-कश्मीर में 564 छापेमारी कर एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारियां हुई है।

केरल में 1,000 निरीक्षणों में घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडर जब्त किए गए है।

मध्य प्रदेश- राज्य में 1,200 छापों के दौरान 1,800 सिलेंडर पकड़े गए है इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों की टीमों ने लगभग 2,500 रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर औचक निरीक्षण किया है।

विदेश मंत्रालय की ओर से क्या बताया गया?

वैश्विक मंच पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है कि विदेश मंत्री ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि काजा कलास के निमंत्रण पर ईयू विदेश मामलों की परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पश्चिम एशिया के हालात और ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव पर विशेष चर्चा की गई, तथा संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया गया।

पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक से 400 की मौत

काबुल। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुलअमान, अरजान कीमत, खैरखाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मोशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि काबुल में किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। अफगानिस्तान सरकार के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि यह हमला स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 9 बजे हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हॉस्पिटल 2000 बेड का है। इसे भारी नुकसान हुआ है। मीडिया की टीमें जब वहां पहुंचीं तो अस्पताल के कुछ हिस्सों में तब भी आग लगी हुई थी। करीब 30 से ज्यादा शव स्ट्रेचर पर बाहर निकाले जा रहे थे। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि वहां बहुत ज्यादा मरीज थे, इसलिए मृतकों और घायलों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है।

भारत बोला- काबुल अस्पताल पर हमला जनसंहार है

भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने इस हमले को कायरतापूर्ण और जनसंहार करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह एक बेहद अमानवीय और अनैतिक हिंसक कृत्य है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान गई। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि जिस जगह को किसी भी हालत में सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता, उसे निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। बयान में पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि वह इस हमले को सैन्य कार्रवाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। भारत ने कहा, पाकिस्तान का यह घिनौना हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर खुला हमला है और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। यह पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के पुराने पैटर्न को दिखाता है, जिसमें वह अपनी आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी सीमाओं के बाहर हिंसक कदम उठाता रहा है। भारत ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है।

पश्चिम एशिया संकट : पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से की बात, होर्मुज समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (17 मार्च) को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. दोनों नेताओं के बीच पश्चिमी एशिया में बने तनाव को लेकर भी चर्चा हुई. भारत ने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की. पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है. पीएम मोदी ने होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा और निर्बाध आवाजाही के मुद्दे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की. साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने की बात दोहराई.

पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. प्रधानमंत्री ने कहा, हमने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए सभी हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा. हम होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमत हुए. हम क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे. इससे पहले सरकार ने उनक खबरों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के बदले में भारत द्वारा जब्त किए गए तीन तेल टैंकरों को छोड़े जाने की मांग कर रहा है. सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि यह रिपोर्ट निराधार है और भारत तथा ईरान के अधिकारियों के बीच इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है. भारत होर्मुज स्ट्रेट से 20 से अधिक भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों का सुरक्षित लाने के लिए तेहरान के संपर्क में है. दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद शनिवार तड़के भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी वाहक जहाज, शिवालिक और नंदा देवी, 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर गए.

खरखौदा की राजस्व सम्पदा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त - डीटीपी अजमेर सिंह

सोनीपत।

जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) अजमेर सिंह ने बताया कि जिला में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों को प्रारंभिक चरण में ही ध्वस्त करने के लिए उपायुक्त सुशील सारवान के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को खरखौदा की राजस्व सम्पदा में आईटीआई चौक के साथ लगती 5.5 एकड़, एनएच-334बी पर हिल वाटर पार्क के साथ लगती 10.5 एकड़ तथा गोपालपुर रोड़ पर 03 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 450 मीटर लम्बा रोड़ नेटवर्क, सीवरेज लाईन, अवैध रास्तों की डिमार्केशन, 1 प्रोपर्टी डीलर ऑफिस व 20 डीपीसी को जिला प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त किया गया। डीटीपी अजमेर सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। ऐसी कॉलोनियों में सरकार द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, सीवरेज या बिजली प्रदान नहीं की जाती। इससे आपकी मेहनत की कमाई जोखिम में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कॉलोनी नियमानुसार स्वीकृत है अथवा नहीं। डीटीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी अवैध कॉलोनी के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा जिले के सभी क्षेत्रों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी विकसित करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कार्रवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय सोनीपत, प्रथम तल, एच.एस.वी.पी कॉम्पलैक्स, सैक्टर-15, सोनीपत में सम्पर्क कर सकते है।

"अवैध कॉलोनियों में न खरीदें प्लाट, अधिक जानकारी के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय में सम्पर्क करें

केसी त्यागी ने छोड़ी जदयू, नीतीश कुमार को रायसभा चुनाव के बाद लगा बड़ा झटका

पटना। राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के एक दिन बाद ही नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के सलाहकार और पूर्व राज्यसभा सांसद के.सी. त्यागी ने मंगलवार को पार्टी छोड़ दी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वह जल्द ही अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वह बिहार छोड़ अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रूप से दिखाई देंगे। बता दें कि केसी त्यागी 2003 में समता पार्टी के साथ जेडीयू के विलय के बाद से ही इससे जुड़े हुए थे। वह जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। एक लिखित बयान में उन्होंने कहा, जेडीयू का गठन 30 अक्टूबर, 2003 को समता पार्टी और जनता दल के विलय से हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस इसके अध्यक्ष थे और मैंने पार्टी के महासचिव के रूप में उनके साथ काम किया। मैंने शरद यादव और नीतीश कुमार के साथ पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम किया, और पार्टी के मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने आगे कहा, पार्टी का सदस्यता अभियान समाप्त हो चुका है और इस बार मैंने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है। दलितों, किसानों और कृषि श्रमिकों, जिनमें समाज के वंचित वर्ग भी शामिल हैं, के हितों से संबंधित व्यापक वैचारिक मुद्दों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पहले की तरह ही दृढ़ है। नीतीश कुमार के प्रति मेरा व्यक्तिगत सम्मान भी अपरिवर्तित है, जो लगभग आधी सदी तक मेरे साथी रहे। बता दें कि केसी त्यागी ने पत्र जारी कर बताया है कि वह 22 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल प्लानिंग का खुलासा कर सकते हैं। त्यागी ने कहा कि उनकी राजनीति में कोई वैचारिक बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वे डॉ. राममनोहर लोहिया, चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से प्रेरित होते रहेंगे। गौरतलब है कि एक साल पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद पार्टी में केसी त्यागी की भूमिका काफी कम हो गई थी। पार्टी ने कई बार उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया था। पार्टी ने हाल ही में नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की उनकी एकतरफा मांग पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी।

गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि अगर ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया, तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ई-केवाईसी की जरूरत सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है, जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि यह कोई नया नियम नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है, वह पुराने अभियान का ही हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा न हो। यदि आप एक सामान्य एलपीजी ग्राहक हैं और आपने पहले अपना ई-केवाईसी करवा लिया है, तो आपको यह प्रक्रिया दोबारा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिनका रिकॉर्ड अब तक अपडेट नहीं हुआ है।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस सख्त, सोफिया फिरदौस समेत तीनों विधायकों को किया निलंबित

नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीन विधायकों रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को वोट दिया था, जिसके चलते कांग्रेस और बीजद के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने तीनों बागी विधायकों को निलंबित करते हुए कहा कि इन विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक व्हिप का उल्लंघन किया है, जो पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बयान जारी कर कहा, तीनों विधायकों ने न सिर्फ पार्टी के निर्देशों को नहीं माना बल्कि पार्टी और इसकी विचारधारा के हितों के खिलाफ काम किया। इसका संज्ञान लेते हुए तीनों विधायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि तीनों पर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है और इन्हें पार्टी से निष्कासित करने पर भी विचार किया जा सकता है। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष अरबिंद दास ने बताया कि मामले की समीक्षा की जा रही है। ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी गई है। भक्त चरण दास ने विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर हैरानी जताई और कहा कि उन्हें इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। भक्त चरण दास ने कहा कि बागी विधायकों को विधानसभा में पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बैठने की इजाजत नहीं होगी।

नाटो देश ईरान जंग में साथ नहीं देना चाहत- ट्रम्प

हम उनकी रक्षा करते हैं, वे मदद नहीं कर रहे, अब किसी की जरूरत नहीं

वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान में नाटो देशों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य सफलता हासिल की है और वह किसी भी सहयोग के बिना भी अपने अभियान को आगे बढ़ा सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि नाटो के कई सहयोगी देशों ने अमेरिका को साफ बता दिया है कि वे ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहते। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस फैसले पर कोई हैरानी नहीं है। उनके अनुसार नाटो लंबे समय से एकतरफा व्यवस्था बन गया है, जिसमें अमेरिका दूसरे देशों की सुरक्षा पर भारी खर्च करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही देश अमेरिका का साथ नहीं देते।

नाटो पर ट्रंप का तीखा हमला

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका हर साल अरबों डॉलर खर्च कर नाटो देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके बावजूद जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वही देश पीछे हट जाते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले से ही लगता था कि नाटो एक वन-वे स्ट्रीट की तरह है। यानी अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा करता है, लेकिन बदले में उसे वही समर्थन नहीं मिलता।

ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का दावा

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका और इस्राइल की संयुक्त कार्रवाई से ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया गया है। ट्रंप के अनुसार ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रडार सिस्टम को भी नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के कई शीर्ष सैन्य नेता अब सक्रिय नहीं हैं। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और उसे किसी भी देश की मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नाटो ही नहीं बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की मदद के बिना भी अमेरिका अपने सैन्य अभियान को जारी रखने में सक्षम है। उनके अनुसार अमेरिका ने अब तक जो सैन्य सफलता हासिल की है, उससे साफ हो गया है कि वह अकेले भी अपने लक्ष्य पूरे कर सकता है।

महिला आरक्षण अधिनियम पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो : मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू से कहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों और रूपरेखा पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए। रिजीजू द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र का जवाब देते हुए, खरगे ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सितंबर 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार रात रिजीजू को लिखे पत्र में कहा, 30 महीने बाद, सरकार संवैधानिक संशोधन के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने के लिए मेरे और मेरी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करने का अवसर तलाश रही है। कुछ दिन पहले आपने मुझसे इस मामले पर बात की थी। खरगे ने कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसा कि राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने भी कहा है कि कांग्रेस का विचार है कि सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जहां सभी विपक्षी दलों के साथ इस तरह की रूपरेखा पर चर्चा की जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऐसी सर्वदलीय बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाएगी। यह संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम परंपराओं को ध्यान में रखते हुए होगी। सरकार संभवतः लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की संभावना तलाश रही है। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बीते सप्ताह पीटीआई-भाषा से कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते अब तक कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन संसद द्वारा 2023 में पारित कानून में संशोधन की संभावना तलाशने की योजना बनाई जा रही है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया गया था, लेकिन यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। यदि परिसीमन प्रक्रिया से पहले ही कानून को लागू करने का प्रस्ताव वास्तव में आता है, तो संविधान में एक और संशोधन की आवश्यकता होगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक (106वां संविधान संशोधन) सितंबर 2023 में पारित किया गया, जो अब कानून बन चुका है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) सीट आरक्षित करने का प्रावधान है।